



Neutral Citation No.- 2026:AHC:127676

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

रिट-सी संख्या - 23500/2026

श्रीमती नेत्रावती एवं अन्य

..... याची

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य एवं 5 अन्य

..... प्रतिवादी

याची के अधिवक्ता: जय सिंह यादव

प्रतिवादी के अधिवक्ता: मु.स्था.अधि., रवि शंकर त्रिपाठी

न्यायालय संख्या - 49

माननीय न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह

1. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता, प्रतिवादी संख्या 4 के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य प्रतिवादीगणके लिए विद्वान स्थायी अधिवक्ता को सुना।
2. वर्तमान रिट याचिका के माध्यम से, याचीगण ने प्रतिवादीगण को उनके शांतिपूर्ण वैवाहिक जीवन में हस्तक्षेप न करने का निर्देश देने वाली परमादेश की प्रकृति की एक रिट हेतु तथा सुरक्षा प्रदान करने हेतु एक निर्देश हेतु भी प्रार्थना की है।
3. याचीगण के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि दोनों याचीगण अशिक्षित हैं और इस प्रकार, उनके पास अपनी वयस्कता की आयु दर्शाने हेतु कोई हाईस्कूल प्रमाणपत्र नहीं है। तथापि, आधार कार्ड की प्रतियां रिट याचिका के अनुबंध संख्या 1 तथा 2 के रूप में संलग्न हैं जो दोनों को वयस्क दर्शाती हैं। आर्य समाज, सहसों, प्रयागराज द्वारा जारी विवाह उत्प्रेषण रिट याचिका के अनुबंध-3 के रूप में संलग्न किया गया है। याचीगण के विद्वान अधिवक्ता ने आगे यह तर्क दिया है कि प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा याची संख्या 2 के विरुद्ध मुकदमा अपराध संख्या 82/2026, धारा 87 भा.न्या.सं., थाना-हजरतपुर, जिला-बदायूं के रूप में दर्ज कराई गई प्र.सू.रि. को इस न्यायालय की समन्वय-पीठ द्वारा स्थगित किया गया है, तथापि, इसकी प्रति इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं की गई है क्योंकि आदेश पोर्टल पर अपलोड नहीं किया गया है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. **लता सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य, 2006 आपराधिक एल.जे. 3309** में, अंतर-जातीय विवाह करने वाले लड़के तथा लड़की के माता-पिता द्वारा उत्पीड़न के एक प्रकरण से निपटते समय, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने देश भर के प्रशासन/पुलिस अधिकारियों को निम्नलिखित शब्दों में निर्देश जारी किए हैं:-

"यह एक स्वतंत्र तथा लोकतांत्रिक देश है, और एक बार जब कोई व्यक्ति वयस्क हो जाता है तो वह जिससे चाहे उससे विवाह कर सकता है। यदि लड़के या लड़की के माता-पिता ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह को स्वीकार नहीं करते हैं तो अधिकतम जो वे कर सकते हैं वह यह है कि वे बेटे या बेटी के साथ सामाजिक संबंध तोड़ सकते हैं, लेकिन वे धमकी नहीं दे सकते या हिंसा के कृत्य नहीं कर सकते या उकसा नहीं सकते तथा ऐसे अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करने वाले व्यक्ति को परेशान नहीं कर सकते। हम, इसलिए, निर्देश देते हैं कि देश भर में प्रशासन/पुलिस प्राधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई लड़का या लड़की जो वयस्क है, किसी वयस्क महिला या पुरुष के साथ अंतर-जातीय या अंतर-धार्मिक विवाह करता है, तो जोड़े को किसी के द्वारा परेशान नहीं किया जाए या धमकियों या हिंसा के कृत्यों के अधीन नहीं किया जाए, तथा जो कोई भी ऐसी धमकियां देता है या परेशान करता है या स्वयं या अपने उकसावे पर हिंसा के कृत्य करता है, उसके विरुद्ध पुलिस द्वारा दांडिक कार्यवाही स्थापित करके कार्रवाई की जाए तथा विधि द्वारा उपबंधित अनुसार ऐसे व्यक्तियों के विरुद्ध और कठोर कार्रवाई की जाए।"

5. **भगवान दास बनाम राज्य (एनसीटी दिल्ली), (2011) 6 SCC 396** में, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तर 28 तथा 29 में इस प्रकार धारित किया:-

"28. अक्सर प्रेम में पड़ने वाले युवा जोड़ों को कंगारू अदालतों के क्रोध से बचने हेतु पुलिस लाइनों या संरक्षण गृहों में शरण लेनी पड़ती है। हमने लता सिंह प्रकरण में यह धारित किया है कि "इज्जत" हत्याओं में कुछ भी "सम्मानजनक" नहीं है, तथा वे सामंती मानसिकता वाले कट्टर व्यक्तियों द्वारा किए गए बर्बर तथा क्रूर हत्याओं के अतिरिक्त कुछ नहीं हैं। हमारी राय में इज्जत हत्याएं, चाहे किसी भी कारण से हों, मृत्युदंड की अधिकारी दुर्लभतम मामलों की श्रेणी में आती हैं। इन बर्बर, सामंती प्रथाओं को समाप्त करने का समय आ गया है जो हमारे



राष्ट्र पर एक कलंक हैं। ऐसे अपमानजनक, असभ्य व्यवहार के लिए यह एक निवारक के रूप में आवश्यक है। "इज्जत" हत्याएं करने की योजना बना रहे सभी व्यक्तियों को यह जान लेना चाहिए कि फांसी उनका इंतजार कर रही है।"

6. विद्वान स्थायी अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी उपर्युक्त अवलोकन तथा निर्देश उत्तर प्रदेश राज्य में लागू किए जा रहे हैं तथा इस चरण में इस न्यायालय द्वारा कोई और निर्देश जारी किया जाना आवश्यक नहीं है क्योंकि यह याचीगण की मात्र आशंका है कि निजी प्रतिवादीगण हिंसा का कोई कृत्य कर सकते हैं और/या याचीगण को परेशान कर सकते हैं।
7. प्रकरण के तथ्यों तथा परिस्थितियों पर विचार करते हुए, लेकिन प्रकरण के गुण-दोष पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, रिट याचिका इस निर्देश के साथ अंततः निस्तारित की जाती है कि याचीगण, विवाहित जोड़े होने के नाते, साथ रहने के लिए स्वतंत्र हैं तथा किसी भी व्यक्ति को उनके शांतिपूर्ण रहन-सहन में हस्तक्षेप करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि याचीगण के शांतिपूर्ण रहन-सहन में कोई बाधा उत्पन्न होती है, तो याचीगण इस आदेश की एक प्रति के साथ संबंधित वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक या पुलिस अधीक्षक से संपर्क करेंगे, जो प्रकरण की जांच करेंगे तथा आवश्यक कार्रवाई करेंगे।
8. याचीगण को यह भी निर्देश दिया जाता है कि उपर्युक्त विवाह, यदि पंजीकृत नहीं है, उत्तर प्रदेश विवाह पंजीकरण नियम, 2017 के प्रावधानों के अनुसार आज से दो महीने के भीतर पंजीकृत किया जाए और यदि याचीगण निर्धारित समय के भीतर विवाह पंजीकृत कराने में असफल रहते हैं, तो यहां प्रदान की गई सुरक्षा प्रभावी होना बंद हो जाएगी।
9. याचीगण को आगे यह निर्देश दिया जाता है कि वे इस न्यायालय की समन्वय-पीठ द्वारा याची संख्या 2 के विरुद्ध दांडिक कार्यवाही को स्थगित करने वाले आदेश की प्रमाणित प्रति आज से दस दिन की अवधि के भीतर इस आदेश के प्रभावी अनुपालन हेतु संबंधित थाने के समक्ष तामील करें।
10. यह स्पष्ट किया जाता है कि इस न्यायालय ने याचीगण द्वारा दावा किए गए विवाह की वैधता और/या उनके विवाह प्रमाणपत्र की वास्तविकता या याचीगण की सही आयु का न्यायनिर्णयन नहीं किया है। यह आगे स्पष्ट किया जाता है, यह आदेश याचीगण को विधि के अनुसार स्थापित किसी भी कार्रवाई या कार्यवाही के विरुद्ध सुरक्षा देने हेतु पारित नहीं किया गया है।



11. चूंकि याचिका प्रारंभिक चरण में ही निस्तारित की जा रही है, इससे व्यथित कोई भी व्यक्ति इसके रिकॉल हेतु आवेदन करने के लिए स्वतंत्र है, यदि आदेश तथ्यों को दबाकर या छुपाकर या गलत अभिकथनों पर प्राप्त किया गया हो।
12. तथापि, यह आदेश पुलिस अधिकारियों के समक्ष लंबित किसी भी जांच, यदि कोई हो, के मार्ग में बाधा नहीं बनेगा।
13. यदि याचीगण द्वारा कोई तथ्य छुपाया गया है तथा आदेश प्रतिवादी संख्या 4 की अनुपस्थिति में पारित किया जा रहा है, तो प्रतिवादी संख्या 4 के लिए इस आदेश के रिकॉल की मांग करते हुए एक आवेदन दाखिल करने का विकल्प उपलब्ध होगा।

(न्यायमूर्ति कुणाल रवि सिंह)

17 जून, 2026

सुमित एस.